साप्ताहिक

डाक पंजीयनः म.प्र./भोपाल/4-479/2019-21

RNI-MPHIN/2015/72544

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 12 अप्रैल 2021, वर्ष-7, अंक-02

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 8 रुपए

» रायसेन के पीएम आवास की हितग्राही से बातचीत का वीडियो पीएम को भेजा

अभिनेता अनुपम खेर को भाया मप्र का गांव

अभिनेता बोले-साफ-सफाई ने मेरी आंखें खोल दीं

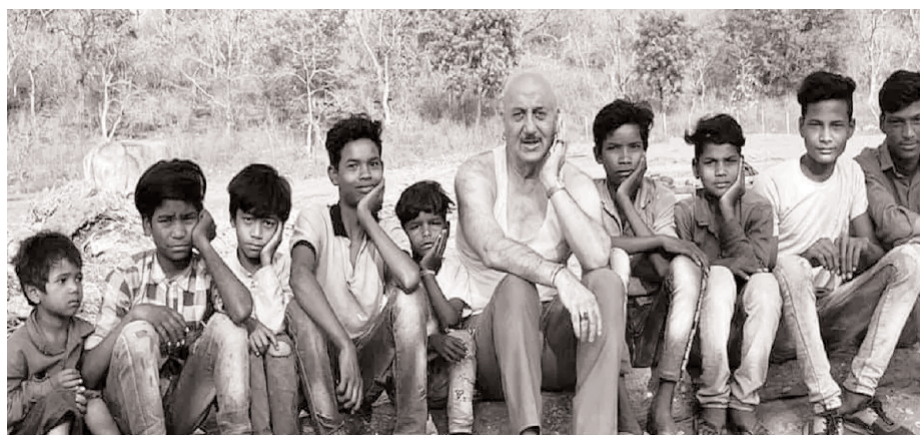

जिले में 51,404 पीएम आवास

जिले में ग्रामीण क्षेत्र में 69,336 पीएम आवास स्वीकृत किए गए हैं। जिसमें से 51,404 आवास पूर्ण हो गए हैं तथा 17,931 आवासों के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। औबेदुल्लागंज जनपद अंतर्गत 4027 आवास पूर्ण व 1469 प्रगतिरत हैं। बाड़ी में 10779 पूर्ण, 2501 प्रगतिरत, बेगमगंज में 7164 पूर्ण, 2479 प्रगतिरत। गैरतगंज में 5695 पूर्ण, 2486 प्रगतिरत, सांची में 5704 पूर्ण व 2697 प्रगतिरत हैं। सिलवानी में 9149 पूर्ण, 3915 प्रगतिरत हैं, उदयपुरा जनपद में 8886 पूर्ण व 2385 प्रगतिरत हैं।

अमित सोनी, रायसेन। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर को रायसेन जिले का इमलिया गोंडी गांव भा गया। वो यहां अपनी शॉर्ट फिल्म हेप्पी बर्थ डे की शूटिंग के लिए आए हैं। गांव की साफ सफाई देखकर वो बोले-यहां के लोगों ने मेरी आंखें खोल दी। यहां के ग्रामीणों के साथ पीएम आवास के बारे में बातचीत की। फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा-गरीब भाई बहनों को फायदा हो रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी का धन्यवाद। यहां की साफ सफाई और साफ सुथरे वातावरण ने उनके आंखें और दिमाग के चक्षु खोल दिए। दूसरी तस्वीर शेयर करते हुए अनुपम खेर ने लिखा भारत के गांवों का

वातावरण अभी भी साफ सुथरा और सादगी से भरा है। शूटिंग के दौरान अच्छा लग रहा है इन जगहों को देखना और यहां के सीधे सादे लोग लोगों से मिलना। अनुपम खेर ने गांव के छोटे-छोटे बच्चों के साथ ली गई अपनी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर कीं। उन्होंने पीएम आवास योजना के तहत बने एक घर को देखकर वहां रहने वाली बच्ची रचना उइके से बात की। रचना ने बताया कि 2018-19 में उन्हें ये मकान मिला है। पहले घर कच्चा था। अब इस पक्के घर में अच्छा लगता है। बातचीत का वीडियो खेर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा-भोपाल से दूर एक छोटे से गांव में शूटिंग के दौरान एक घर की दीवार पर कुछ लिखा था। उसे पढ़ने के बाद मैंने उस परिवार की सदस्या रचना से बात की। रचना के उत्तर सुनकर मन प्रसन्न हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीब भाई बहनों को फायदा हो रहा है।

इनका कहना है

फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने औबेदुल्लागंज जनपद की ग्राम पंचायत इमलिया गोंडी में प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के हितग्राही सदस्या से बातचीत का वीडियो इलेक्ट्रानिक मीडिया में डाला है।

-पीसी शर्मा, जिला पंचायत, सीईओ रायसेन

» खेती और पशुपालन में नया अध्याय सिद्ध होगा मिशन अर्थ

» अब भोपाल में देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमन प्रयोगशाला

मप्र में पैदा होंगी 90% बछिया

सीएम ने किया डिजिटली लोकार्पण

प्रदेश के कृषि उत्पाद देश ही नहीं दुनिया में धूम मचाएंगे

985 सामुदायिक गौशालाओं का लोकार्पण

145 सामुदायिक गौशालाओं का शिलान्यास

1821 पशु आश्रयों का किया गया श्रीगणेश

2632 पशु आश्रयों का भी किया शिलान्यास

अरविंद मिश्र, भोपाल

देश की दूसरी बड़ी प्रयोगशाला केंद्रीय वीर्य संस्थान भोपाल के भदभदा में स्थापित की गई है। 47 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से स्थापित होने वाली इस परियोजना की लागत में 60 फीसदी केंद्रांश और 40 प्रतिशत राज्यांश शामिल है। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत अत्याधुनिक सेक्स सॉरटेड सीमन प्रोडक्शन प्रयोगशाला का डिजीटली लोकार्पण किया है। इस दौरान ग्राम पंचायतों में 260 करोड़ की लागत से बनी 985 सामुदायिक गौ-शालाओं का लोकार्पण और 50 करोड़ रुपएसे बनने जा रहीं 145 सामुदायिक गौ शालाओं का शिलान्यास भी किया गया। भोपाल के केन्द्रीय वीर्य संस्थान में सेक्स सॉरटेड सीमन फेसिलिटी परियोजना में निकट भविष्य में प्रदेश में गिर, साहीवाल, थारपारकर गाय और मुर्रा भैंसों आदि उच्च अनुवांशिक गुणवत्ता की 90 फीसदी बछिया ही पैदा होंगी। बछियों की संख्या अधिक होने से दूध उत्पादन में अभूतपूर्व बढ़ोत्तरी होगी और निराश्रित बछड़ों की संख्या भी नहीं बढ़ेगी। साथ ही उच्च गुणवत्ता के दुधारू पशु मिलने से किसानों को अधिक मात्रा में दूध मिलेगा और उनकी आमदनी में भी उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी होगी। दुग्ध उत्पादन में प्रदेश की सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने की रफ्तार बढ़ जाएगी। पहली प्रयोगशाला उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्थापित की गई है। मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम और सर्विस प्रोवाइडर कम्पनी के मध्य हुए अनुबंध के अनुसार शुरू के तीन सालों में क्रमशः 3-3 और दो लाख सीमन डोजेज का उत्पादन कर पशुपालकों को उपलब्ध कराया जाएगा।

लिखेंगे पशुपालन का न्याय अध्याय

मुख्यमंत्री ने कहा है कि सीमन प्रयोगशाला, किसान उत्पादक संगठन, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम, मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना, मवेशियों के लिए यूनिक आईडी जैसी गतिविधियां प्रदेश में कृषि और पशुपालन का नया अध्याय लिखेंगी।

पशुओं को यूनिक आईडी देने में मप्र नंबर वनः राज्य के मवेशियों का भी अब यूनिक आईडी होगा। योजना के तहत गौ-भैंस वंशीय पशुओं के कान में टैग लगाया जा रहा है। टैग पर बारह अंकों का आधार नंबर अंकित है। जिसे इनॉफ साफ्टवेयर में अपडेट किया जा रहा है। साफ्टवेयर में मवेशियों का लेखा जोखा होगा। जो ऑनलाईन भी उपलब्ध होगा। प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 45 लाख गौ-भैंस वंशीय पशुओं की टैगिंग की जा चुकी है। इस योजना में मध्यप्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है।

इनका कहना है

राज्य सरकार किसान की आय को दोगुनी करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। खेती-पशुपालन-उद्यानिकी- मछली पालन- सहकारिता को समग्रता में लेकर फसलों के विविधीकरण, फूड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और सही मार्केटिंग से हमारे प्रदेश के उत्पाद देश ही नहीं दुनिया में धूम मचाएंगे। मिशन अर्थ के अंतर्गत भदभदा भोपाल में 47 करोड़ 50 लाख की लागत से देश की दूसरी अत्याधुनिक सीमन उत्पादन प्रयोगशाला का लोकार्पण किया है।

शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री

18 पुरस्कारों के साथ पंचायतों ने बढ़ाया प्रदेश का गौरव

भोपाल। मध्यप्रदेश की पंचायतों में किए गए नवाचार, उत्कृष्ट कार्य और केंद्रीय योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए देशभर में उत्कृष्ट पाई गई पंचायतों ने प्रदेश का गौरव देशभर में बढ़ाया है। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2021 के लिए 15 पुरस्कार मप्र की झोली में आए हैं। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड और चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड के लिए भी तीन पुरस्कार मप्र की झोली में आए हैं। केंद्र ने अवार्ड के लिए पंचायतों के प्रस्तावों के मूल्यांकन के बाद जिला और राज्य स्तरीय मूल्यांकन के आधार पर चयन किया है। मप्र की दो जिला पंचायतों सागर और बैतूल को सामान्य श्रेणी में पचास-पचास लाख के पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। ब्लॉक स्तर की दो पंचायतों रतलाम की जौरा व सीहोर की सीहोर जनपद पंचायत को 25 लाख का पुरस्कार मिलेगा। ग्राम पंचायत श्रेणी में दस लाख और बाल हितैषी पंचायत को पांच लाख का पुरस्कार दिया जाएगा।

नीमच को स्वच्छता पुरस्कारः पं. दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण स्वच्छता को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर नीमच की सावन पंचायत का चयन किया गया है।

मप्र को 11 पुरस्कार मिलेः ग्राम पंचायत स्तर पर मप्र को राष्ट्रीय स्तर के 11 पुरस्कार मिले हैं। इनमें सीधी के पनवार चौहान को सामान्य श्रेणी का, पश्चिम निमाड़ में सोमगांन खुद को थीमेटिक मार्जिनालाईन्ड सेक्शन इंप्रूवमेंट के लिए, उमरिया के दोदका, भोपाल भाईसौंदा, सीहोर के मेतवाड़ा का सामान्य श्रेणी में, नीमच की सावन को थीमेटिक श्रेणी में, जबलपुर की सिहोदा सीधी की बागवारी को सामान्य श्रेणी, धार के कुंदा को थीमेटिक नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए, जबलपुर की बिखारबा को सामान्य श्रेणी पुरस्कार मिलेगा।

हमने तीन साल में मरनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना में जो कार्य किया उसे राज्य और केंद्र की टीम ने सराहा। साथ ही हमारे द्वारा बनाई गई नराग्रह वाटिका को भी टीम द्वारा सराहना मिली है। जिसके आधार पर बैतूल को यह पुरस्कार मिला है।

एमएल त्यागी, सीईओ, जिपं बैतूल

जिले में होने वाली सामान्य सभा की बैठकों में लिए गए निर्णय और उनमें सभी वर्गों की सह भागगिता तथा कराए गए विकास कार्यों के सफल क्रियान्वयन के आधार पर सागर जिले को पुरस्कार से नवाजा गया है।

इच्छित गढ़पाले, सीईओ, जिपं सागर

» जिले में तीसरी फसल मूंग की बोवनी तेज

» गोदामों पर लगा ताला, भटक रहे अन्नदाता

नर्मदापुरम में किसानों को खल रही खाद की कमी

प्रदीप शर्मा, नर्मदापुरम

पूरे जिले में गेहूं की कटाई के तुरंत बाद इस समय तीसरी फसल के रूप में मूंग की बोवनी जारी है। बोवनी के लिए किसानों को खाद की जरूरत है, लेकिन शासन की गोदाम और निजी क्षेत्र में खाद का टोटा बना हुआ है। इस कारण ज्यादातर गोदामों पर ताला लगा रहने से किसान भटक रहे हैं। मजबूर होकर किसानों को निजी दुकानों पर मंहगे दाम में खाद खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है। किसान जब खाद लेने पहुंच रहे हैं तो गोदाम पर ताला लटका लगा मिल रहा है। जिससे बोवनी प्रभावित होने की संभावना किसान बता रहे हैं। जो गोदाम में स्टाक था वह किसान ले गए, लेकिन अभी भी आधे से अधिक किसान रह गए हैं। किसान संघ व अन्य किसानों का कहना है बिना खाद के मूंग की अच्छी पैदावार संभव नहीं है।

आठ हजार टन की दरकार

जिले में खाद का संकट गहराने लगा है। शासन की संस्थाओं में उपलब्धता बताई जा रही है कि गोदामों में 6 हजार टन खाद उपलब्ध है, लेकिन जिस प्रकार मूंग का रकबा बढ़ रहा है उस हिसाब से जिले में कुल आठ हजार टन खाद की जरूरत है। जो मांग के हिसाब से कम है। इसलिए किसानों को चिंता सताने लगी है।

20 फीसद बोवनी

संभाग में अभी तक 20 फीसद बोवनी होना बताया जा रह है। जिसमें पहले बोवनी कर चुके किसानों के लिए अब खाद की आवश्यकता बनी हुई है। लेकिन उन्हें समय पर खाद नहीं मिलने से परेशान होना पड़ रहा है। खाद वितरण केंद्रों पर किसान बार-बार जा रहे हैं तो ताला लगा मिल रहा है। खाद की पूर्ति समय पर नहीं होने से क्षेत्र के किसानों में नाराजगी बढ़ रही है।

उपलब्धता में से हो गया वितरण

जो उपलब्धता बताई जा रही है वह पुराना रिकॉर्ड है। जिसमें से काफी मात्रा में वितरण हो गया है। जो बचा हुआ है वह मांग के हिसाब से बेहद कम है। संभाग के तीनों जिलों में खाद की कमी होने से किसानों के सामने अपनी फसल में खाद की पूर्ति करने में दिक्कतें हो रही हैं। इस कमी की बजह से मूंग के पैदावार पर असर पड़ने की संभावना है।

इनका कहना है

जितेंद्र सिंह, संयुक्त संचालक कृषि

यह सच है कि इस समय तेजी से मूंग की बोवनी चल रही है। मूंग की फसल को खाद की जरूरत है। जो किसान पहुंच भी रहे हैं उन्हें खाद दिया जा रहा है। सभी गोदामों पर खाद की उपलब्धता है।

प्रदीप गरैवाल, जिला विपणन अधिकारी

खाद जिले में उपलब्ध है। जिस गोदाम में ताला लगा हुआ था उस समय हो सकता है कर्मचारी बैंक गए हों। क्योंकि स्टाफ की कमी है। खाद वितरण प्रभारी छुट्टी पर होने के कारण वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी। जल्द ही व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। किसान चिंता न करें।

गणेश गौर, किसान नेता

किसानों को जब भी जरूरत रहती है। तब हर बार परेशान होना पड़ता है। प्रशासन हर बार कहता है कि पूर्ति हो रही है लेकिन पूर्ति नहीं हो पाती। जब किसान को खाद की जरूरत रहती है तब उसे चक्कर लगाने को या फिर ज्यादा राशि चुकाकर खरीदी करना पड़ता है।

राकेश गौर, जिलाध्यक्ष, राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ

खाद समय पर मिलना चाहिए। यदि समय पर पूर्ति नहीं हुई तो आंदोलन को मजबूर होना पड़ेगा। इन नेताओं ने बताया कि किसानों को निजी क्षेत्र से 1200 रुपए की जगह 1500 में लेने को मजबूर होना पड़ रहा है।

हरदा में मूंग की रिकॉडतोड़ बोवनी

» ग्रीष्मकालीन मूंग बोवनी का लक्ष्य 1.25 लाख हेक्टेयर

» कृषि विभाग ने अनुदान पर दिया 1000 क्विंटल बीज

कृषि मंत्री की अपील पर जिजगांव के किसान ने बोया 50 एकड़ में मूंग

इधर, प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल के गृह जिला हरदा में रबी सीजन की फसल कटाई के बाद उपज बिकने से पहले ग्रीष्मकालीन मूंग की बोवनी शुरू हो चुकी है। जिले में अब तक 45 हजार हेक्टेयर रकबे में मूंग की फसल बोवनी हो चुकी है। यह बोवनी का आंकड़ा उन किसानों का है। जिनके पास स्वयं के पानी के साधन हैं। नहर से सिंचाई करने वाले किसान बोवनी के लिए तैयारी कर रहे हैं। वे नहरों के पानी से सिंचाई में जुटे हैं। जबकि कृषि विभाग ने इस वर्ष ग्रीष्मकालीन मूंग बोवनी का लक्ष्य 1 लाख 25 हजार हेक्टेयर रखा है। जिले में तेजी से मूंग बोवनी की जा रही है। वहीं कृषि विभाग द्वारा किसानों को बोवनी के लिए अनुदान पर 1000 क्विंटल मूंग का बीज वितरित किया गया है।

23 मार्च को छूटा नहरों में पानी

जिले की नहरों में 23 मार्च की रात से तवा डेम से पानी छोड़ा गया है। इसके बाद 25 मार्च को जिले की नहरों में पानी पहुंच चुका है। फिलहाल किसान नहरों से छोड़े गए पानी से खेतों में सिंचाई कर रहे हैं। जल संसाधन विभाग ने 23 मार्च की रात से तवा डेम से 500 क्यूसेक पानी छोड़ा। जिसे बाद में बढ़ाया गया। जिले की नहरों में 50 दिन तक पानी दिया जाएगा।

जिले में मूंग की फसल को लेकर किसानों का रुझान बढ़ा है। जिजगांव निवासी उन्नत किसान संजय माकवे ने बताया कि कृषि मंत्री हमारे जिले के हैं और उन्होंने क्षेत्र के किसानों से मूंग की बावनी करने की अपील की। मंत्री की अपील पर हमने इस बार 50 एकड़ में मूंग की बोवनी की है। उनका कहना है कि मंत्री के प्रयासों से इस बार नहर में पानी भी पर्याप्त आ रहा है, हमें आशा है कि फसल अच्छी होगी।

इस प्रकार रहा जिले में मूंग का रकबा

वर्ष	जिले में रकबा
2021	45000 हेक्टेयर
2020	82500 हेक्टेयर
2019	12130 हेक्टेयर
2018	12310 हेक्टेयर
2017	8500 हेक्टेयर
2016	27120 हेक्टेयर
2015	35250 हेक्टेयर

(आंकड़े कृषि विभाग के अनुसार)

इनका कहना है

जिले में अब तक 45 हजार हेक्टेयर रकबे में ग्रीष्मकालीन मूंग की बोवनी की गई है। ग्रीष्मकालीन मूंग की बोवनी जारी है। इस वर्ष 1 लाख 25 हजार हेक्टेयर में मूंग की बोवनी का लक्ष्य रखा गया है।

-कपिल बेड़ा, सहायक संचालक, कृषि विभाग, हरदा

जल संसाधन विभाग की चेतावनी

किसान विभाग के घोषित क्षेत्र अनुसार ही मूंग की बोवनी करें। इसके अतिरिक्त क्षेत्र में मूंग की बोवनी करने से सिंचाई में परेशानी आ सकती है। बिना अनुमति सिंचाई करने पर मोटर अथवा पंप जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

राकेश दीक्षित, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग

» एसीएस ने सागर में गौशाला और नर्सरी का किया निरीक्षण, बोले

» स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने गौकाष्ठ, कंडे निर्माण के संबंध में बताया

» गायों के लिए विकसित किए गए चारागाह को भी दिखाया गया

पहले हमें अपनी निर्भरता को समझना होगा तभी हम बन पाएंगे आत्मनिर्भर

संवाददाता, सागर

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव ने सीहोरा ग्राम पंचायत पहुंचकर गौशाला का निरीक्षण किया। गौशाला के निरीक्षण के दौरान स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने उनके द्वारा किए जा कार्य गौकाष्ठ, कंडे निर्माण के संबंध में बताया।

साथ ही गायों के लिए विकसित किए गए चारागाह को भी दिखाया। स्वसहायता समूह की महिलाओं ने उनके द्वारा निर्मित की गईं पीपीई-किट एवं मास्क को भी दिखाया। इसकी अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव ने सराहना की। श्रीवास्तव ने कहा कि आत्म निर्भर के लिए पहले हमें अपनी निर्भरता को समझना होगा, तभी हम आत्म निर्भर बन पाएंगे।

स्व-सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा तैयार किए जा रहें उत्पादों को अमेजन ऐप पर भी उपलब्ध कराया जाए। इसके संबंध में निर्देश दिए। श्रीवास्तव ने ग्राम चौकी में किए गए पौधारोपण का भी निरीक्षण किया। जिला पंचायत सीईओ डॉ. इच्छित गढ़पाले ने सागर जिले में किए जा रहे गौशाला संचालन, नवाचार एवं अन्य कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। एसीएस ने सागर जिले में किए जा रहे कार्यों एवं नवाचारों की प्रशंसा की।

रतौना में बनाई जाएगी आदर्श गौशाला

रतौना डेयरी फार्म में जिले की आदर्श गौशाला स्थापित की जाएगी। उक्त निर्देश कलेक्टर दीपक सिंह ने गौशाला की समीक्षा बैठक में दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि रतौना डेयरी फार्म में 20 एकड़ भूमि चिन्हित कर आदर्श गौशाला बनाई जाए। जिसमें गौवंश को रखा जा सके। उन्होंने कहा कि जिले में स्व-सहायता समूह के माध्यम से जो 26 गौशालाएं संचालित की जा रही हैं। उनके समूह के प्रमुखों को गौशाला के उत्कृष्ट संचालन के लिए प्रशिक्षण जिला स्तर पर आयोजित किया जाए। जिससे उनको आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रशिक्षण दिया जा सके।

भिंडः मेहगांव जनपद की ग्राम पंचायत महाराजपुरा का चौंकाने वाला कारनामा

विजयपुर बीएमओ और उनके रिटायर पिता मनरेगा के मजदूर

भिंड। ग्राम पंचायतों के विकास और स्थानीय जरूरतमंद लोगों को काम देने के लिए मनरेगा कानून लागू किया गया है, लेकिन अब यह ग्राम पंचायत से जुड़े जिम्मेदारों की जेब भरने का साधन बन गया है। ताजा मामला मेहगांव जनपद की ग्राम पंचायत महाराजपुरा का है। महाराजपुरा पंचायत में श्योपुर जिले के विजयपुर में पदस्थ बीएमओ डॉ. प्रदीप बराहदिया और उनके रिटायर हेडमास्टर पिता सहित परिवार के सदस्यों को मनरेगा मजदूर बना दिया है। बीएमओ के पिता ने पोर्टल से यह जानकारी निकलवाई है। उन्होंने जनपद पंचायत मेहगांव से सूचना के अधिकार में यह जानकारी मांगी तो वहां से उन्हें गोलमोल जवाब देकर लौटा दिया गया।

पूरा परिवार बना मजदूरः मेहगांव के महाराजपुरा ग्राम पंचायत हाल ग्वालियर निवासी रिटायर हेडमास्टर सरमन लाल बराहदिया ने बताया कि पोर्टल पर ग्राम पंचायत ने उन्हें, पत्नी कस्तूरी देवी, बड़े बेटे विजयपुर बीएमओ डॉ. प्रदीप बराहदिया, डॉ. प्रदीप की पत्नी विमला देवी, छोटे बेटे ग्वालियर जीवाजी यूनिवर्सिटी में काउंसलर दिनेश बराहदिया, उत्तर मध्य रेलवे झांसी में इंजीनियर बेटी नीलम और 18 वर्षीय

नाती प्रिंस को मनरेगा का मजदूर बताया गया है।

इंजीनियर बेटी का दो बार लिखा नामः रिटायर हेडमास्टर बराहदिया का कहना है कि मनरेगा के पोर्टल पर ग्राम पंचायत की ओर से उनकी इंजीनियर बेटी नीलम का दो बार नाम लिखा गया है। नीलम को परिवार में सब गुड्डी के नाम से पुकारते हैं तो मनरेगा के लिए नीलम का नाम दूसरी बार गुड्डी लिखा गया है।

2015-2016 का फर्जीवाड़ाः बराहदिया ने कहा कि यह फर्जीवाड़ा वर्ष 2015 से 2016 तक हुआ है। इसके अलावा बाद के वर्षों की जानकारी के लिए सूचना के अधिकार से आवेदन किया है। बराहदिया का कहना है ग्राम पंचायत ने नौकरीपेशा लोगों को मनरेगा का मजदूर बनाने का काम किया है। इससे पहले गांव के विनय, शिवमोहन और राधा ने शिकायत की है।

इनका कहना है

मैंने यह जानकारी मनरेगा के पोर्टल से हासिल की है। इसको लेकर मैं मेहगांव ग्राम पंचायत में सूचना के अधिकार के तहत आवेदन देकर विधिवत जानकारी मांगी है। लेकिन जनपद पंचायत से जानकारी देने में गोलमोल जवाब दिया जा रहा है। सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगने का आवेदन करते ही ग्राम पंचायत सरपंच ने घर आकर प्रलोभन देने की कोशिश की है।

सरमन लाल, बराहदिया, रिटायर हेडमास्टर

होशंगाबाद के आठ गांव बनेंगे प्रमुख पर्यटन केंद्र, 60 करोड़ रुपए वार्षिक आय का अनुमान

पंकज शुक्ला, होशंगाबाद

तवा बेसिन के किनारे बसे आठ गांवों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की तैयारी जिला प्रशासन ने की है। इन गांवों का सर्वे कराकर पर्यटन की संभावना को देखते हुए कार्ययोजना शासन स्तर पर भेज दी गई है। यह पहला मौका है जब गांवों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की कार्ययोजना तैयार की गई है। खास बात ता यह है कि इन आठों गांवों में पर्यटन से होने वाली आय का आंकलन भी किया गया है। साठ करोड़ रुपए की वार्षिक आय होने का अनुमान है। पर्यटन विकास का पूरा खाका कलेक्टर धनंजय प्रताप सिंह की देखरेख में खींचा गया है। तवा नदी के फैलाव इटारसी, नर्मदापुरम, सिवनी व पचमढ़ी में आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करेगा।

इन गांवों का चयन

तवा जलाशय के समीप बसे मालनी, कोटमील, चटुआ, खारपावद, उरदोन, खापा, परसापानी और खकरापुर गांव को पर्यटन गतिविधियों के लिए चुना गया है। शासन स्तर से अनुमति मिलते ही यहां व्यवस्थाएं की जाएंगी। इन गांवों के युवाओं को रोजगार मिलेगा। साथ ही वे आर्थिक रूप से संपन्न भी हो सकेंगे। वर्तमन में ये गांव वनक्षेत्रों में आते हैं और यहां के अधिकांश लोग खेती पर ही निर्भर हैं।

पर्यटकों के लिए ये गतिविधियां

तवा रिसोर्ट, कैनाल इनलेट के पास वाटर स्पोर्टस सेंटर और शैक्षिक सुविधाएं के रूप में बयोस्फीयर इंटरप्रिटेशन सेंटर और इमेजिनारियम (भविष्य को प्रदर्शत करने वाले एंटोनियम), ईको-फ्लोटलेज (अस्थायी ईको विलेज), बैक वाटर हाउसबोट,

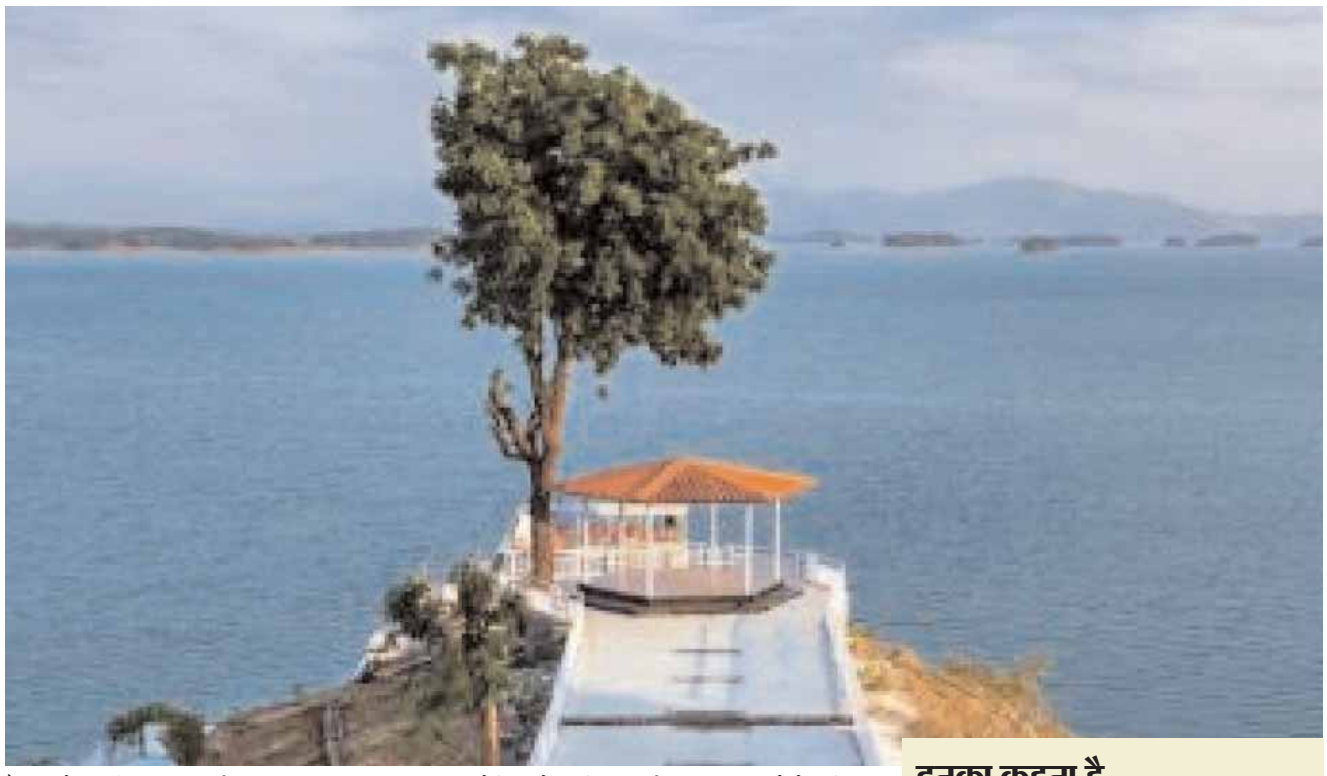

कैनालबोट, जंगल लॉज, ट्री टॉप लॉज, वॉच टॉवर के रूप में विकसित होंगे।

ईको टूरिज्म सेवाओं की संभावना

प्रशासन की ओर से जो कार्ययोजना तैयार की गई है उसमें बताया गया है कि उपबेसिन में अद्वितीय वनस्पतियां और जीव प्रजातियों हैं। साथ ही उपबेसिन में कृषि मछली पकड़ना व ईको टूरिज्म सेवाओं की प्रचुर संभावना है। अद्वितीय प्राकृतिक, स्वच्छ, निर्मल, पुरातन के साथ ही स्थानीय लाभ व त्वरित संपर्क होने से उत्तारखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और केरा के इको टूरिज्म प्रतिस्पर्धी राज्यों के लिए एक पसंदीदा स्थल बनेगा।

इनका कहना है

तवा उपबेसिन क्षेत्र में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। जलाशय का माप करीब दो सौ वर्ग किमी के आसपास है। इससे सटे गांवों में भी पर्यटन विकास की संभावना को देखते हुए कार्ययोजना तैयार की गई है।

धनंजय सिंह, कलेक्टर, नर्मदापुरम

मप्र बिजली के क्षेत्र में स्थापित कर रहा नए आयाम

प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दूरदर्शी और संकल्पवान नेतृत्व में मध्यप्रदेश बिजली के क्षेत्र में नित नये आयाम स्थापित कर रहा है। प्रदेश में विद्युत क्षेत्र के विकास और विस्तार के लिए सभी आवश्यक और सुविचारित कदमों का उठाया जाना इन आयामों को छूने के पीछे है। परिणाम भी सामने है और वह यह कि 31 दिसंबर, 2020 की स्थिति में प्रदेश की उपलब्ध विद्युत क्षमता 21 हजार 361 मेगावॉट हो जाना।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दूरदर्शी और संकल्पवान नेतृत्व में मध्यप्रदेश बिजली के क्षेत्र में नित नये आयाम स्थापित कर रहा है। प्रदेश में विद्युत क्षेत्र के विकास और विस्तार के लिए सभी आवश्यक और सुविचारित कदमों का उठाया जाना इन आयामों को छूने के पीछे है। परिणाम भी सामने है और वह यह कि 31 दिसंबर, 2020 की स्थिति में प्रदेश की उपलब्ध विद्युत क्षमता 21 हजार 361 मेगावॉट हो जाना। इसी दिन प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक 15 हजार 425 मेगावॉट शीर्ष मांग की पूर्ति भी सफलतापूर्वक की गई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में उपलब्ध विद्युत क्षमता में 1 हजार 426 मेगावाट वृद्धि का लक्ष्य है। प्रदेश में पारेषण हानियां भी अब मात्र 2.59 प्रतिशत रह गई हैं, जो पूरे देश में न्यूनतम हानियों में से एक है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 6006 करोड़ यूनिट विद्युत प्रदाय किया गया, जो पिछले वर्ष से 9 प्रतिशत अधिक है। प्रदेश में विद्युत व्यवस्था प्रणाली की मजबूती के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में कई उल्लेखनीय कार्य किए गए। इनमें उपलब्ध विद्युत क्षमता में 394 मेगावाट की वृद्धि, 14 नए अति उच्च दाब उप केन्द्रों की स्थापना, एक हजार 72 सर्किट किलोमीटर अति उच्च दाब और एक हजार 645 किलोमीटर उच्च दाब लाइनों का निर्माण, 11 नये 33/11 किलोवाट उप केन्द्रों की स्थापना एवं 2005 वितरण ट्रांसफार्मरों की स्थापना के कार्य प्रमुख हैं। इससे इस अवधि में उपभोक्ताओं की संख्या में एक लाख 90 हजार की वृद्धि हुई है। आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश रोडमैप में भविष्य की विद्युत माँग की सुचारू आपूर्ति के लिए पारेषण प्रणाली के विस्तार कार्यक्रम में 4000 करोड़ रुपए की लागत के ग्रीन एनर्जी कॉरीडोर एवं टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक निविदाओं के जरिए अति उच्च दाब उप केन्द्रों एवं उससे संबंधित लाइनों का निर्माण शामिल किए गए हैं। ग्रीन एनर्जी कॉरीडोर में 90 प्रतिशत काम पूरा हो गया है। जून 2021 तक अधिकांश काम पूरा कर लिया जाएगा। टैरिफ आधारित 2000 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश के जरिए पहली परियोजना का कार्य प्रगतिरत है, जिसे वर्ष 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन अवधि में बिजली उपभोक्ताओं की तकलीफ को महसूस कर उनके हित में अनेक निर्णय लिये। इन निर्णयों से उपभोक्ताओं को 1000 करोड़ से अधिक की राहत मिली। ऐसे सभी घरेलू उपभोक्ता, जो संबल योजना के हितग्राही हैं एवं जिनके माह अप्रैल, 2020 में देयक की राशि 100 रूपये तक थी, से मई, जून एवं जुलाई इन तीन माहों में सिर्फ 50 रूपए प्रतिमाह की राशि का ही भुगतान लिया गया। प्रदेश के ऐसे सभी घरेलू उपभोक्ता, जिनके माह अप्रैल, 2020 में देयक की राशि 100 रुपए तक थी, उनके मई, जून एवं जुलाई, 2020 में देयक राशि 100 रूपये से 400 रुपए तक आने पर उनसे इन तीन माहों में मात्र 100 रुपए प्रतिमाह की राशि का भुगतान लिया गया। प्रदेश के ऐसे घरेलू उपभोक्ता, जिनकी माह अप्रैल, 2020 में देयक राशि रुपए 100 से अधिक परन्तु रुपए 400 या उससे कम थी, उनके मई, जून एवं जुलाई, 2020 में देयक राशि 400 रुपए से अधिक आने पर उनसे इन तीन माहों में देयक की आधी राशि का ही भुगतान लिया गया। शेष आधी राशि का भुगतान आस्थगित किया गया है। प्रदेश के निम्न दाब गैर घरेलू एवं निम्न दाब औद्योगिक उपभोक्ताओं तथा उच्च दाब टैरिफ एचवी-3 उपभोक्ताओं से माह अप्रैल, मई एवं जून 2020 के विद्युत देयकों में स्थायी प्रभार की वसूली को आस्थगित कर यह राशि माह अक्टूबर, 2020 से मार्च, 2021 के विद्युत देयकों के नियमित भुगतान के साथ, छः समान किश्तों में बिना ब्याज के ली जाने की सुविधा दी गई है। प्रदेश के उच्च दाब सहित सभी उपभोक्ताओं द्वारा लॉकडाउन के चलते अप्रैल एवं मई माह में देय विद्युत बिलों का भुगतान सामान्य नियत तिथि तक करने पर एक प्रतिशत की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी गई। इसमें निम्न दाब उपभोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन राशि अधिकतम रूपये दस हजार मात्र तथा उच्च दाब उपभोक्ताओं के लिए अधिकतम रूपये एक लाख मात्र निर्धारित की गई। उपभोक्ताओं को अपनी संविदा मांग में कमी करने की सुविधा भी दी गई। इसका लाभ लेने पर उनके नियत प्रभार और न्यूनतम प्रभार में कमी आई। मुख्यमंत्री के इस एक साला कार्यकाल में विद्युत उपभोक्ताओं को राहत देने का सिलसिला यहीं नहीं रुका। एक किलोवाट तक के भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए अगस्त, 2020 तक की बकाया राशि को आस्थगित कर सिर्फ चालू माह के देयक ही जारी किए जा रहे हैं। सभी पात्र घरेलू उपभोक्ताओं से भी उनकी पहली 100 यूनिट तक की मासिक खपत पर मात्र 100 रुपए लिए जा रहे हैं। अनुसूचित जाति/जनजाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 30 यूनिट तक की मासिक खपत पर सिर्फ 25 रूपये ही देने होते हैं। अंतर राशि का भार राज्य शासन वहन कर रहा है। इससे प्रति माह लगभग एक करोड़ घरेलू उपभोक्ता लाभांवित हो रहे हैं। वर्तमान रबी सीजन में कृषि उपभोक्ताओं को दिन के समय अधिक बिजली देने के लिए फ्लेक्सी प्लान लागू किया गया है। कृषि कार्य के लिए लगभग 22 लाख कृषि उपभोक्ता को फ्लैट दरों पर बिजली दी जा रही है। एक हेक्टेयर तक की भूमि एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के 8 लाख कृषि उपभोक्ता को मुफ्त बिजली दी जा रही है। विद्युत शिकायतों के निराकरण की प्रक्रिया में जन-भागीदारी सुनिश्चित की गयी है। उपभोक्ताओं से हर स्तर पर सीधे संवाद की व्यवस्था की गई है। विद्युत प्रदाय की शिकायतों के जल्द हल के लिए केन्द्रीयकृत कॉल सेंटरों को सुदृढ़ किया गया है। वर्ष 2020-21 में प्राप्त सभी साढ़े 21 लाख से ज्यादा शिकायतों को हल किया गया है। करीब 3 लाख 80 हजार उपभोक्ताओं से शिकायतों के हल का संपर्क में औसत संतुष्टि प्रतिशत 98.39 पाया गया है। गलत देयकों से संबंधित 33 हजार से अधिक शिकायतों को शिविर लगाकर मौके पर ही दूर किया गया है। किसानों को शीघ्र स्थाई सिंचाई पंप कनेक्शन दिए जाने के लिये लागू स्वयं का ट्रांसफार्मर योजना में किसान अपने खर्च से, निर्धारित मापदंड अनुसार 73 हजार 257 ट्रांसफार्मर स्थापित कर चुके हैं। शहरी क्षेत्र में मीटरीकरण, वितरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण तथा आईटी कार्यों की 50 परियोजनाओं के सभी कार्य पूर्ण हो गए हैं।

आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की संजीवनी बनेगा पर्यटन

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संकल्प और साहसी निर्णयों ने आज मध्यप्रदेश को विकासशील राज्य की अग्रिम पंक्ति में लाकर खड़ा किया है। उनके प्रयासों और संकल्प से आज पर्यटन क्षेत्र आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश की संजीवनी के रूप में उभरा है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि शिवराज सिंह चौहान और मध्यप्रदेश एक दूसरे के पूरक है। नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य और अद्भुत स्थापत्य कला के धनी मध्यप्रदेश का गौरवशाली इतिहास और समृद्ध संस्कृति पूरे भारत में अद्वितीय है। जिस तरह हीरे की असली परख जौहरी को ही होती है उसी तरह मध्यप्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार और विकास की असीम संभावनाओं को तलाशने का हुनर मुख्यमंत्री में ही है। उन्होंने न सिर्फ प्रदेश के नैसर्गिक और लुभावने स्थलों को पर्यटन के लिए विकसित किया बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा किए। अब पर्यटन सिर्फ मनोरंजन नहीं रहा बल्कि रोजगार, स्थानीय संस्कृति और खान-पान, कला और स्थापत्य कला का केंद्र-बिंदु भी बनके उभरा है। मुख्यमंत्री के निर्देशन में पर्यटन विभाग ने कोविड के बाद की परिस्थितियों के अवसरों को तलशाना जारी रखा। नित नए प्रयासों और नवाचारों से मध्यप्रदेश में पर्यटन की संभावनाओं को ढूंढने के उद्देश्य को लेकर सतत प्रयास किया। पर्यटन के प्रमुख क्षेत्र वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म, लेइश्यरू टूरिज्म और पिलग्रिमेज टूरिज्म की सभी संभावनाओं को विकसित किया गया। सभी उम्र के व्यक्तियों की रुचियों को ध्यान में रखकर गतिविधियाँ आयोजित की गई। रूरल टूरिज्म, हेरिटेज वॉक, इंस्टाग्राम मांडू टूर, साइकिल टूर, आर्ट एंड क्राफ्ट बाजार, म्यूजिकल कंसर्ट और फूड बाजार जैसे नवाचार किए गए। मध्यप्रदेश एडवेंचर टूरिज्म का हॉटस्पॉट बनके उभरा है। यहां का प्राकृतिक सौंदर्य और मनभावन वातावरण अनायास ही ट्रेकिंग, सफारी और कैंपिंग के शौकीनों को आकर्षित करता है। एडवेंचर टूरिज्म की इन्हीं संभावनाओं को देखते हुए पर्यटन विभाग ने प्रदेशभर में 30 से ज्यादा कैंपिंग साइट विकसित किए गए हैं। पर्यटकों के हॉलिडे को एक्टिव हॉलिडे में परिवर्तित करते हुए टूर-डे सतपुड़ा, हेरिटेज रन, पचमढ़ी मॉनसून मैराथन जैसे कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू की गई है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में बैलून सफारी, टाइग्रेस ऑन ट्रेल और भोपाल में प्रदेश के पहले ड्राइव इन सिनेमा की स्थापना आदि प्रमुख नवाचार रहे हैं। वर्तमान में भी मध्यप्रदेश को 365 डेज का टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने का संकल्प लेकर सतत प्रयास किए जा रहे हैं। वार्षिक आयोजनों की श्रृंखला में 5 जल महोत्सवों और ओरछा महोत्सव का आयोजन किया गया है। वेब सीरीज पंचायत, गुल्लक और धाकड़ के फिल्मांकन से मध्यप्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। इसी दिशा में ग्रामीण पर्यटन की संकल्पना पर वैल्यू फॉर मनी डेस्टिनेशन के विकास कार्य में स्थानीय लोगों को भागीदार बनाया जाएगा। इससे क्षेत्र विशेष की संस्कृति और धरोहर से पर्यटक परिचित हो सकेंगे। मध्यप्रदेश को वैलनेस एंड माइंडफुल टूरिज्म के केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में भी निरंतर प्रयास जारी है।

कोरोना के खिलाफ संकटमोचक बना आयुष विभाग

राम किशोर कावरे आयुष (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री

अनादिकाल से भारतीय संस्कृति में रोगों के निदान के लिए आयुर्वेद से उपचार कारगर माना गया है। चरक भारतीय चिकित्सा विज्ञान (आयुर्वेद) के मानक ग्रंथ हैं। आयुर्वेद ग्रंथ की रचना आचार्य चरक ने की थी। भारतीय जीवन शैली में आयुर्वेद शामिल रहा है। वर्तमान कोरोना संकट के समय आयुष ने संकटमोचक की भूमिका निभाकर रोग से लड़ने और मुक्त होने में सहायक बना है। मध्यप्रदेश सरकार ने दुनिया के समक्ष आए सबसे बड़े संकट कोविड-19 से मुक्ति के लिए आयुष पद्धति को अपनाया। कोविड-19 में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में विभिन्न औषधि एवं आहार विहार को अपनाकर कोरोना पर नियंत्रण प्राप्त किया। इस संकटकाल में मध्यप्रदेश शासन के आयुष विभाग ने जिस तरह सक्रियता से कार्य किया, वह उल्लेखनीय रहा। आयुष विभाग ने आयुष चिकित्सालयों, औषाधालयों का उन्नयन करने के साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और जिला चिकित्सालयों में आयुष विंग की स्थापना कर आयुष सेवा का प्रभावी क्रियान्वयन किया। भारत सरकार के सहयोग एवं मार्गदर्शन में अनेक स्तरों पर आयुर्वेद संबंधी शोध का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में भविष्य को दृष्टि में रखकर आयुर्वेद की शिक्षा को भी विस्तार दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री जीवन अमृत योजना में प्रदेश के 1773 औषधालयों, 23 चिकित्सालयों, 36 आयुष विंग एवं 9 आयुष महाविद्यालय से संबद्ध चिकित्सालय द्वारा रोग प्रतिरोधक दवाओं का वितरण किया गया। यही नहीं, लॉकडाउन अवधि में 1847 दलों द्वारा होम्योपैथी, यूनानी, आयुर्वेद दवा एवं काढ़ा (रोग प्रतिरोधक) का वितरण घर-घर पहुंच कर किया गया। आयुष विभाग ने सबसे अहम कार्य प्रवासी मजदूरों की विशेष रूप से स्क्रीनिंग, स्वास्थ्य परीक्षण एवं औषधि वितरण का किया। कोविड-19 के क्वारेंटाइन, पॉजिटिव रोगियों, आयुष महाविद्यालय एवं कोविड केयर सेंटर में भर्ती रोगियों को 'आरोग्य कषायम-20' का सेवन कराए जाने से 39 हजार से ज्यादा रोगियों को स्वास्थ्य लाभ मिला। पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, भोपाल द्वारा 'आरोग्य कषायम-20' का लक्षण रहित एवं अल्प लक्षण वाले कोविड-19 रोगियों में प्रभावों का आंकलन करने के लिए रेन्डमाइज्ड एवं नियंत्रित अध्ययन किया गया। भारत सरकार ने मध्यप्रदेश में हुए इस शोध की प्रशंसा की है। अब पीएमओ द्वारा इसका विश्लेषण किया जा रहा है। कोरोना केयर सेंटर होम्योपेथिक केन्द्र पर केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद नई दिल्ली के तत्वावधान में लक्षण रहित कोविड पॉजिटिव रोगियों को स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकाल के साथ चिन्हित होम्योपैथी औषधियों के तुलनात्मक प्रभाव का अध्ययन किया जा रहा है। रोगियों में वायरल लोड का अनुसंधान शासकीय होम्योपैथी महाविद्यालय, भोपाल द्वारा किया जा रहा है। इसी क्रम में भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय से अधिसूचित मध्यप्रदेश के 4 जिले मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर और शहडोल में पाए जाने वाले आयुर्वेद औषधि पौधों का सर्वेक्षण एवं मानकीकरण पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, भोपाल द्वारा किया जा रहा है। विभाग के सभी मेडिकल, पैरामेडिकल, शासकीय एवं निजी आयुष महाविद्यालय के अंतिम वर्ष एवं स्नातकोत्तर के लगभग 12 हजार विद्यार्थियों को कोरोना संक्रमण संबंधी प्रशिक्षण ऑनलाईन दिया गया। भोपाल जिले के फंदा एवं बैरसिया ब्लाक में मधुमेह के बचाव के लिए कार्यक्रम आयोजित कर आयुर्वेद आधारित दिनचर्या, आहार-विहार एवं आयुर्वेद दवा से मधुमेह पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए जागरूक किया जाएगा। इसके बाद प्राप्त परिणामों का विश्लेषण किया जाएगा। आयुष चिकित्सों के दल द्वारा घर-घर जाकर उनके स्वास्थ्य का सर्वे किया जा रहा है। अब तक 30 ग्रामों के 37 हजार परिवारों के करीब 2 लाख व्यक्तियों का सर्वेक्षण कर सर्वे रिकार्ड का डॉटाबेस सॉफ्टवेयर में दर्ज किया गया है। सर्वे परिणाम के आधार पर चिकित्सा शिविर, जागरूकता शिविर एवं योग शिविर का 15 दिवस के अंतराल में आयोजित किया जाएगा। वर्ष 2021 में प्रदेश के चिकित्सा सुविधा विहीन क्षेत्रों में करीब 13 हजार चिकित्सा शिविरों का आयोजन कर साढ़े 9 लाख से अधिक रोगियों को आयुष चिकित्सा का लाभ दिया गया। कोविड-19 के रोगियों को वितरित आयुष औषधि से लाभांवितों की संख्या मिलाकर 5 करोड़ 1 लाख 50 हजार 81 रही।

साइलो फुल

11 दिन में खरीदी बंद, अनाज से भरी ट्रालियों की लगी दो किमी लंबी लाइन

गेहूं की बंपर खरीद, सुस्त परिवहन से बढ़ी परेशानी

वंदना बृजेश परमार, उज्जैन। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के 11 दिन में ही जिले का सबसे बड़ा खरीदी केंद्र साइलो, मानपुर पूरी क्षमता से भर गया है। आखिरी दिन केंद्र से दो किमी लंबी कतार लगी रही। इस दिन किसानों से 485 टन अतिरिक्त खरीदी की गई। साइलो केंद्र प्रभारी हर्षित दुबे के अनुसार केंद्र की क्षमता 50 हजार टन है, लेकिन परिवहन नहीं होने से केवल 5 हजार टन की जगह थी। खरीदी की शुरुआत 27 मार्च से हो गई थी। केंद्र पर जिला थोक उपभोक्ता सहकारी सेवा समिति के 11 और सेवा सहकारी संस्था चंदेसरा के 9 गांव के किसान पंजीकृत हैं। जिला आपूर्ति नियंत्रक एमएल मारू के अनुसार साइलो केंद्र पर गेहूं बेचने के लिए पंजीकृत किसानों में से जितने किसान शेष हैं, उनके संबंध में समिति को निर्देश दिए हैं। वे अपने स्तर पर मंडी में तौलकांटे लगवाएगी। दो दिन में व्यवस्था करने व संसाधन जुटाए जाएंगे।

अब तक 239 केंद्रों से 126099 टन खरीदी

जिले में गेहूं खरीदी के लिए प्रशासन ने 239 केंद्र बनाए हैं। जिला आपूर्ति नियंत्रक के अनुसार सभी केंद्रों पर खरीदी शुरू हो गई है। अब 18314 किसानों से 126099 टन गेहूं खरीदे गए हैं। इनमें से 53 फीसदी का परिवहन हो गया है। शेष गेहूं खरीदी केंद्रों पर खुले मैदान में रखा है। इसके अलावा पिछले साल खरीदे गए गेहूं का भी परिवहन नहीं हो पाया है।

सर्वर डाउन, भुगतान के लिए अब भी इंतजार

खरीदी शुरू होने के 11 दिन बाद भी किसानों को भुगतान नहीं मिल पा रहा है। अफसरों का कहना है पूरा सिस्टम ऑनलाइन है। भोपाल से अब तक जिले के लिए 57 हजार किसानों को एसएमएस भेजे गए हैं। रोज औसत 8 हजार एसएमएस भेजे जाते हैं। इसी तरह भुगतान भी ऑनलाइन होगा। सर्वर में खराबी के कारण अब तक भुगतान शुरू नहीं हो सका। 92110 किसानों ने 835705 टन गेहूं बेचे थे पिछले साल। उन्हें 1570.27 करोड़ भुगतान हुआ था।

देश में जल्द मिलेगा परागण रहित मक्का का बीज

» देशभर के किसानों को सस्ते दामों पर मिलेगा बीज
» दिसंबर और जनवरी छोड़कर पूरे साल होगी खेती

संवाददाता, करनाल/भोपाल

मक्का उत्पादक किसानों और इसके स्वादिष्ट एवं पोषक तत्वों से भरपूर व्यंजनों को पसंद करने वालों के लिए अच्छी खबर है। देश में प्रथम परागण रहित (मेल स्टेराइल) मक्का बीज बनाने में सफलता मिलने के बाद इसके ट्रायल का अंतिम वर्ष चल रहा है। यदि इस शोध में सफलता मिली तो भविष्य में मक्का उत्पादक किसानों को सरकारी अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से न्यूनतम दर पर बीज प्राप्त हो सकेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान-पूसा नई दिल्ली व चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र करनाल ने संयुक्त रूप से अनुसंधान कर मक्का की हाईब्रिड किस्म एचएम-4 को मेल स्टेराइल में परिवर्तित किया है। अब तक भारत में जितनी भी मक्का किस्में बेबीकार्न के लिए इस्तेमाल की जाती हैं सभी परागण वाली हैं। बेबीकॉर्न उगाने के लिए मक्का के पौधे के ऊपरी हिस्से से फूल तुड़वाने में किसानों को श्रमिक लगाने पड़ते हैं। उनका अतिरिक्त खर्च आता है। यही वजह है कि किसान मेल स्टेराइल बीज पसंद करते हैं। यह विदेशों से आयात होता है, लेकिन आयातित बीज महंगा पड़ता है।

इनका कहना है

हाईब्रिड एचएम-4 किस्म गुणों से भरपूर है और इसमें परागण होता है। उसे बेबीकॉर्न की खेती के लिए मेल स्टेराइल में परिवर्तित किया है। मेल स्टेराइल बीज में परागण नहीं होगा और गुणवत्ता भी बनी रहेगी। दिसंबर व जनवरी छोड़कर पूरे वर्ष उत्तर भारत में इसकी खेती हो सकती है।

डॉ. फिरोज हुसैन, प्रधान वेज्ञानिक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान-पूसा नई दिल्ली

भारत में परागण रहित बीज बनाने पर विशेष काम नहीं हुआ। अब सिजेंटा-5414 किस्म का बीज मिलता है जो विदेश से आयात हो रहा है। 600 रुपए प्रति किलो बीज मिलता है। यदि भारत में बीज उत्पादन किया जाए तो किसान को 200 रुपए किलो तक बीज मिल सकता है।

कंवल सिंह चौहान, पद्मश्री किसान, सोनीपत

2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगी गेहूं की नई किस्में

इधर, 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह प्रयासरत है। इस कार्य में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने एक कदम बढ़ाते हुए गेहूं की 10 और जो कि एक नई किस्म इजाद की है, जिसकी न केवल पैदावार बहुत अच्छी है अपितु ये बीमारी रोधी भी हैं। इसमें 9 किस्में भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल तथा गेहूं की एक किस्म चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने ईजाद की है। इसको लेकर भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल में अखिल भारतीय गेहूं एवं जो अनुसंधानकर्ताओं की 59वीं कार्यशाला का ऑनलाइन आयोजन हुआ। इस कार्यशाला में देश के विभिन्न क्षेत्रों से गेहूं और जौ विज्ञान से जुड़े विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। 2019 के दौरान हुई प्रगति की समीक्षा करने और 2020-21 के लिए अनुसंधान गतिविधियों को खाका तैयार करने के लिए बैठक का आयोजन किया था।

दस किस्मों की पहचान की गई: इस बार देश भर में गेहूं की 10 किस्मों की पहचान की गई है। इसमें उत्तर-पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के लिए एचडी 3292, डीबीडब्ल्यू 187 अगेती बीबीडब्ल्यू 303 और 1270, उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र के लिए एचडी 3293 मध्य क्षेत्र के लिए सीजी 1029 एच आई 1634 प्रदीप क्षेत्र के लिए बीडी-डब्ल्यू 48एच, आई 1633 देर से बोवनी के लिए 1149 उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के लिए खेतों के लिए एक माल्ट जो किस्म डब्ल्यू आरबी 182 की पहचान की गई है।

नई किस्मों की पैदावार बहुत अच्छी है। इन किस्मों की खेती करने से किसानों की आर्थिक स्थिति में क्रांतिकारी सुधार होगा। पहले भारत में उगे जौ का प्रयोग दूसरे देशों में बियर के लिए नहीं होता था, लेकिन यह जौ श्रेष्ठ किस्म है। इससे बेहतर किस्म की बियर बनेगी इससे खासकर दक्षिणी हरियाणा और राजस्थान और मध्यप्रदेश के किसानों को इसका सीधा फायदा होगा।

डॉ. ज्ञानेंद्र प्रताप, निदेशक, राष्ट्रीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान केंद्र

बुंदेलखंड में 'श्वेत क्रांति' लाएगा गोकुल ग्राम

अनिल दुबे, सागर

देश में सूखे के लिए चर्चित बुंदेलखंड को बड़ी सौगात मिली है। केन-बेतवा लिंक के जरिए खेतों में पानी पहुंचाने के लक्ष्य के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने बुंदेलखंड में 'श्वेत क्रांति' का बीड़ा उठाया है। यहां देसी गायों के संरक्षण और पशुपालन को किसानों की आय का प्रमुख जरिया बनाने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार ने यहां गोकुल ग्राम की स्थापना की है। इसके जरिए बुंदेलखंड में थारपारकर, साहीवाल, गिरी सहित अन्य उच्च दुग्ध उत्पादन नस्ल की भैंस का वंश तैयार होगा। दरअसल, केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश का पहला गोकुल ग्राम सागर जिले के रतौना में बनाने का फैसला किया है। इसके लिए राज्य सरकार ने 500 एकड़ जमीन का अलॉटमेंट कर दिया है। इस जमीन पर 600 देसी भारतीय गायों के रहने की व्यवस्था होगी। गौरतलब है कि अभी देश में कुल 20 गोकुल ग्राम हैं। एक गाय के लिए यहां पर रहने, खाने और इलाज की सुविधाएं जुटाने में लगभग एक लाख 70 हजार रुपए खर्च होंगे मतलब गोकुल ग्राम में गायों के लिए कुल दस करोड़ खर्च किए जाएंगे। कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू हो हो गया है। हालांकि लॉकडाउन की वजह से गति धीमी है। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो अब तक गोकुल ग्राम बनकर तैयार हो जाता। यहां पर गायों, बछिया और बछड़ों के लिए अलग-अलग शेल्टर बनाए गए हैं। इन्हें ऐसे बनाया बनाया गया है ताकि गौवंश के लिए ये आरामदायक हों, उनका वेंटिलेशन ठीक से हो। अब मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य हो जो गायों के लिए इस तरह का ग्राम बसने जा रहा है।

- मध्य क्षेत्र का पहला गोकुल ग्रांम सागर का रतौना गांव
- केंद्र से मिल चुकी प्रदेश को राशि
- डेयरी विस्थापन में प्रशासन को होगी आसानी
- गायों के संरक्षण पर राज्य व केंद्र सरकार का पूरा फोकस

अभी 300 गाय, 150 भैंस

अधिकारियों ने बताया कि शुरुआत में थारपारकर नस्ल की गाय गोकुल ग्राम में रखी जाएंगी। इस प्रजाति को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्य किए जाएंगे। फिलहाल में इस प्रजाति की करीब 300 से ऊपर गाय हैं। इसके अलावा डेढ़ सौ के करीब उच्च क्वालिटी की भैंस भी हैं। इसकी खास बात एक यह भी होगी कि यहां पर सिर्फ चुनिंदा गाय ही रखी जाएंगी। मतलब एक ही नस्लों की गाए और सांड होंगे। इन नस्लों की क्रॉस ब्रीडिंग नहीं कराई जाएगी।

दूध उत्पादन पर फोकस

गोकुल ग्राम में गाय उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात जैसे दूसरे राज्यों से लाई जाएंगी। यहां पर 600 गायों में से साठ फीसदी गाय उत्पादन वाली और 40 फीसदी उत्पादन न करने वाले पशु होंगे। इन गायों को कृत्रिम गर्भ धारण कराया जाएगा। गायों के लिए यहां कोरांटीन शेड्स बन गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि गोकुल ग्राम बसाने के पीछे उद्देश्य है कि भारतीय देसी गायों की नस्लों का संरक्षण हो सके।

भारतीय गायों का होगा सेंटर

गोकुल ग्राम विकसित होने के बाद यहां एक एकीकृत भारतीय देसी गायों का सेंटर बनाया जाएगा। यहां पर भारतीय देसी गायों को तैयार करके किसानों और गाय पालकों को उपलब्ध कराई जाएंगी। गोकुल ग्राम के संचालन में अरने वाला खर्च गायों का दूध, जैविक खाद, वर्मी खाद, गौमूत्र बेचकर निकाला जाएगा।

देशी गायों का होगा संरक्षण

राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत प्रदेश का पहला पशु प्रजनन और कृषक एवं कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केन्द्र सागर के रतौना में शुरू किया गया है। 15 करोड़ की लागत से तैयार किए गए केन्द्र का शुभारंभ हाल ही में प्रदेश के पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने किया। यहां 9 करोड़ 70 लाख की लागत से पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, 5 करोड़ से कृषक एवं कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान, छात्रावास, प्रशासनिक भवन और पशु शेड तैयार किया गया है।

13 राज्यों में गोकुल ग्राम

देश में 13 राज्यों में 20 जगह गोकुल मिशन शुरू किया गया है, जिसमें बुंदेलखंड के सागर जिले के रतौना का चयन किया गया है। इससे यहां के पशुपालकों को लाभ मिलेगा। देसी गायों की नस्ल सुधार व दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए कार्य किए जाएंगे। इससे रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

गौ उत्पाद केंद्र बनेगा गोकुल ग्राम

गोकुल ग्राम को गाय उत्पाद का केंद्र बनाया जाएगा। यहां बायोगैस प्लांट से बिजली और सीएनजी उत्पादन भी किया जाएगा। वर्मी कंपोस्ट यानी अच्छी गुणवत्ता की खाद तैयार की जाएगी। गौमूत्र से फिनायल और दवाएं बनाई जाएंगी। गोकुल ग्राम को गौ उत्पाद केंद्र के साथ-साथ गाय अनुसंधान केंद्र के रूप में भी विकसित किया जाएगा।

देश में होंगे 21 गोकुल ग्राम

गत 21 जून 2019 को राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत समेकित मवेशी विकास केंद्र के रूप में 21 गोकुल ग्रामों की स्थापना के लिए राशि मंजूर की गई है। अभी चार गोकुल ग्राम वाराणसी, मथुरा, पटियाला और फोरा में स्थापित हो चुके हैं। शेष 17 गोकुल ग्रामों में काम चल रहा है। योजना के तहत आंध्रप्रदेश में एक, अरुणाचल प्रदेश में एक, बिहार में एक, छत्तीसगढ़ में दो, गुजरात में तीन, हरियाणा में एक, हिमाचल में एक, कर्नाटक में एक, महाराष्ट्र में तीन, मध्यप्रदेश में एक, पंजाब में एक, उत्तर प्रदेश में तीन, उत्तराखंड में एक और तेलंगाना में एक कुल 21 गोकुल ग्राम स्थापित किए जाएंगे।

इनका कहना है

यह केंद्र 1 सितंबर 2019 में बना है। यहां पर फिलहाल 425 पशु हैं, जिनमें से 310 गौवंश और 115 भैंस वंश हैं। केंद्र का सबसे ज्यादा जोर बछिया की संख्या बढ़ाने पर है। इसके लिए यहां सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। यहां पर थारपारकर नस्ल के गौवंश को बढ़ावा देने पर अधिक फोकस है।

-डॉ. एसके पचौरी, प्रभारी,
गोकुल ग्राम रतौना, सागर

भोपाल में सीएजी से रोकेंगे कार्बन उत्सर्जन

संवाददाता, भोपाल

- ऑटो-कार को सीएनजी में शिफ्ट कराने पर 5 हजार
- स्कूल बस को मुफ्त मिलेगी 20 हजार रुपए की गैस
- भोपाल में 1700 वाहन सीएनजी फ्यूल का इस्तेमाल
- भोपाल में पेट्रोल 98.94 रुपए प्रति लीटर मिल रहा
- भोपाल में सीएनजी 72 रुपए प्रति लीटर मिल रही

वाहनों के धुएं से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए अब सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को बढ़ावा देने की तैयारी शुरू हो गई है। भोपाल में मौजूदा पेट्रोल कार और ऑटो रिक्शा को सीएनजी में तब्दील कराने वाले वाहन चालकों को 5 हजार रुपए कीमत की सीएनजी मुफ्त दी जाएगी। वहीं स्कूल बस और ट्रकों में सीएनजी किट लगवाने पर 20 हजार रुपए कीमत की सीएनजी मुफ्त मिलेगी। नए सीएनजी ऑटो पर 2 हजार और सीएनजी कार पर 3 से 5 हजार रुपए तक की गैस मुफ्त मिलेगी। केंद्र और राज्य सरकार के साथ मिलकर सीएनजी डिस्ट्रीब्यूशन का काम करने वाली कंपनी थिंक गैस के मुताबिक भोपाल में सभी सीएनजी फिलिंग स्टेशन पर यह सुविधा मिलेगी। अब तक भोपाल में 15 सीएनजी फिलिंग स्टेशन शुरू हो चुके हैं। पांच निर्माणाधीन हैं, जो अगले दो से तीन माह में चालू हो जाएंगे। ये सभी शहर में हाई ट्रैफिक मोबिलिटी वाले प्रमुख मार्गों पर बनाए गए है। थिंक गैस के प्रेसिडेंट मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट संदीप त्रेहान ने बताया कि भोपाल में वर्तमान में प्रतिदिन 5 हजार किलोग्राम सीएनजी गैस की खपत होने लगी है। अगले तीन माह में इसे 15 हजार किलोग्राम प्रतिदिन तक पहुंचने का अनुमान है। भोपाल में 1700 वाहन सीएनजी फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं।

पेट्रोल से आधी लागत

भोपाल में पेट्रोल कार का प्रति किलोमीटर रनिंग कॉस्ट 5.20 रुपए प्रति किमी हैं। जबकि सीएनजी किट के बाद प्रति किलोमीटर कॉस्ट 2.46 रुपए प्रति किमी है। यदि कोई कार रोजाना 150 किलोमीटर प्रतिदिन चलती है, तो एक साल में सीएनजी से चलने पर 1 लाख 34 हजार 685 रुपए की बचत होती है।

यहां फिलिंग स्टेशन शुरू

डी-मार्ट के पास अयोध्या बायपास, ललिता नगर कोलार, पटेल नगर रायसेन रोड, लांबाखेड़ा बैरसिया रोड, खजूरी सड़क सीहोर रोड, नेहरू नगर पुलिस लाइन, डीआरएम रोड अवधपुरी थाना के पास, केपिटल मॉल होशंगाबाद रोड, अमरावद खुर्द भोपाल बायपास, न्यू सेंट्रल जेल करोंद, 11-मील रतनपुर सड़क आदि।

» खुले बाजार में मिल रहीं ज्यादा कीमतें
» उपार्जन केंद्र पर एक दाना नहीं आया

सरसों के उपार्जन के झंझट से बची सरकार

भोपाल। प्रदेश में इस बार सरकार समर्थन मूल्य पर सरसों का उपार्जन करने से बच गई है। सरकार ने अभी तक प्रदेश में किसी भी उपार्जन केंद्र पर सरसों का एक दाना भी नहीं खरीदा है। क्योंकि खुले बाजार में किसानों को समर्थन मूल्य से ज्यादा के भाव मिल रहे हैं। इस वजह से किसान सरकार को फसल बेचने के लिए नहीं आ रहे है। प्रदेश में ग्वालियर-चंबल में सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन होता है। इस बार यहां मंडियों में किसानों को समर्थन मूल्य से ज्यादा कीमत मिल रही है। जिसकी वजह इस बार प्रदेश के बाहर से व्यापारी आए हैं।

हालांकि सरकार ने सरसों के उपार्जन की तैयारी कर ली थी। जिसके तहत समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीदी का समय चल रहा है, लेकिन ज्यादा कीमत मिलने की वजह से किसान केंद्र पर नहीं आ रहे हैं। शिवपुरी, श्योपुर, भिंड, मुरैना और ग्वालियर की मंडियों में सरसों की खरीदी 5 हजार प्रति क्विंटल से ज्यादा पर हो रही है। जबकि सरसों का समर्थन मूल्य 4650 रुपए है। मंडियों में सबसे ज्यादा खरीदी सरसों की हो रही है। किसानों का कहना है कि जब भाव व्यापारी अच्छा दे रहा है, पैसा भी तत्काल मिल रहा है तो कोई क्यों सरकारी केंद्र पर जाएगा। दूसरा केंद्र पर फसल बेचने के लिए 100 झंझटों का सामना करो। हालांकि सरसों के लिए लाखों किसानों ने पंजीयन कराया है।

उपार्जन केंद्रों पर सन्नाटा

ग्वालियर-चंबल के जिलों में सरसों के लिए खोले गए उपार्जन केंद्रों पर किसान नहीं पहुंच रहे हैं। गेहूं बेचने के लिए किसान पहुंच रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में भी किसान उपार्जन केंद्र छोड़कर मंडियों में सरसों बेचने के लिए जा रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से सरसों के लिए किसानों को मैसेज भेजे जा रहे हैं। सरसों का उपार्जन नहीं होने से सरकार को इस बार बड़ी राहत है। क्योंकि उपार्जन केंद्रों पर हर साल गड़बड़ी की शिकायतें आती है। इस बार इन झंझटों से मुक्ति मिल गई है।

सीएम बोले-प्रदेश में उद्योगों का जाल बिछाना सरकार का संकल्प

एक साल में 12 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य

संवाददाता, भोपाल

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में लघु, कुटीर और मध्यम उद्योगों का जाल बिछे यह मेरा सपना भी है और संकल्प भी। इस स्तर के उद्योग ही रोजगार के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराते हैं। रोजगार आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण का मूल आधार है। राज्य शासन उद्यमियों की मदद के लिए सदैव तत्पर है। इस दिशा में आरंभ की गई स्टार्ट यूअर बिजनेस इन थर्टी डेज योजना का उद्देश्य यही है कि प्रदेश में अपना उद्योग आरंभ करने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई भी परेशानी न आए। हमारा यह लक्ष्य है कि हर महीने प्रदेश के एक लाख लोगों को रोजगार दिलाया जाए। इस प्रकार एक साल में बारह लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में हम निरंतर सक्रिय हैं। लोगों के लिए रोजगार सृजन में लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग राज्य सरकार के सहयोगी ही हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री ने मिशन अर्थ के अंतर्गत प्रदेश के 1891 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के वर्चुअल शुभारंभ के राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

कृषि में रोजगार की अपार संभावनाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना के कठिन काल में आत्म-निर्भर भारत के निर्माण का मंत्र दिया। इसके परिपालन में आत्म-निर्भर

मध्यप्रदेश के निर्माण के लिए विकसित रोडमैप में अर्थ-व्यवस्था और रोजगार प्रमुख आधार स्तंभ हैं। प्रदेश में अधोसंरचना निर्माण, कृषि और खाद्य प्र-संस्करण में उद्यमशीलता और रोजगार के अवसर सृजित करने की अपार संभावनाएं हैं। कोरोना के कठिन काल में प्रदेश के पथ विक्रेताओं और स्व-सहायता समूहों को राज्य शासन द्वारा हरसंभव सहयोग प्रदान किया गया है।

युवा नौकरी देने वाले बने

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के लिए स्व-रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्य से पुरानी योजनाओं की रीपैकेजिंग कर नई मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना आरंभ करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के विकास के लिए जितना योगदान बड़े उद्योगों का है उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका एमएसएमई की है। इसकी महत्ता को स्वीकार करते हुए ही प्रदेश में पृथक एमएसएमई विभाग बनाया गया। मेरा सपना है कि प्रदेश के युवा नौकरी मांगने वाले नहीं रोजगार देने वाले बने। यह सपना लघु, कुटीर और मध्यम उद्योगों से ही साकार हो सकता है।

50 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। प्रदेश में 1891 इकाइयां वर्चुअली आरंभ की जा रही हैं। इनमें 4227 करोड़ का निवेश हुआ है। यह इकाइयां 50 हजार से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 572 इकाइयां मार्च 2021 तक स्थापित हो चुकी हैं। अगले तीन माह में 296 और अगले छह माह में एक हजार 23 इकाइयां स्थापित होंगी।

विकास के नए रास्ते खुलेंगे

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ओमप्रकाश सकलेचा ने कहा कि उद्योग क्षेत्र में बहुत तेजी से तकनीकी बदलाव आ रहा है। वैश्विक स्तर की मांग के अनुसार प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों को कदम से कदम मिलाकर चलने में सक्षम बनाने के लिए मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश में आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। खजुराहो सांसद तथा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि प्रदेश में इतने व्यापक स्तर पर औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से प्रदेश में विकास के नए रास्ते खुलेंगे।

मुख्यमंत्री ने की उद्यमियों से बातचीत

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के उद्यमियों से वर्चुअली संवाद भी किया। नीमच में हनी और हर्बल प्रोडक्ट्स पर केन्द्रित दीर्घायु भव-हनी एण्ड हर्बल इकाई की मीनाक्षी मालव, खरगोन में पीपी बैग निर्माण इकाई के संचालक प्रवीण गुप्ता, बालाघाट में सीड लाख उत्पादन इकाई चलाने वाले महेन्द्रा परधी, सतना में पास्ता और ब्रेड निर्माण इकाई संचालक मुस्कान रावलानी और टीकमगढ़ में आजाद स्टील फर्नीचर के मालिक मोहम्मद शहजाद मंसूरी से बातचीत की।

सीवर के साफ पानी से हराभरा हो रहा शहर

प्रदेश में सीवेज के पानी का उपयोग करने वाला पहला शहर बना ग्वालियर

सीवेज के पानी से गांवों में हरियाली

दिव्या मिश्रा, ग्वालियर

ग्वालियर प्रदेश का एक मात्र ऐसा शहर बन गया है जो शहर से निकले सीवर व नालों के पानी को साफ कर उसका उपयोग हरियाली सहित अन्य कार्यों में कर रहा है। सीवेज के पानी को साफ करने के लिए शहर में एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) लगाए हैं, जिनसे साफ हुआ पानी शहर को हराभरा करने में मददगार साबित हो रहा है।

सीवेज के फिल्टर पानी से पार्कों में पौधों की सिंचाई की जा रही है। इधर, जलालपुर व लालटिपारा पर बनाए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से पानी को साफ कर उसे मुरार व स्वर्णरेखा नदी में छोड़ा जा रहा है। इस पानी को किसान अपनी खेती के उपयोग में ले रहे हैं। अमृत योजना के तहत शहर में पांच स्थानों पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जा रहे हैं। इनमें तीन प्लांट शुरू हो चुके हैं, जबकि दो निर्माणाधीन हैं। जलालपुर स्थित स्वर्णरेखा नदी पर 145 एमएलडी का प्लांट लगाया गया है, जबकि लालटिपारा स्थित मुरार नदी पर 65 एमएलडी का प्लांट बनाया है।

यहां पर सीवेज और नालों में बहकर आ रहे पानी को साफ कर उन्हें नदियों में छोड़ा जा रहा है। इस पानी का उपयोग किसान खेती के लिए कर रहे हैं। साथ ही जल संसाधन विभाग भी नहरों के माध्यम से इस पानी को कई गांवों को दे रहा है। इधर, लालटिपारा स्थित प्लांट से निकला साफ पानी बहकर गोहद के बांध में पहुंच रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र का जलस्तर बढ़ रहा है। इस पानी का उपयोग खेती में भी किया जा रहा है।

इन गांवों में पहुंच रहा पानी

जलालपुर स्थित एसटीपी प्लांट से जलालपुर, अकबरपुर, जमाहर, महू आदि गांवों में खेती के लिए पानी का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही लालटिपारा स्थित 65 एमएलडी के प्लांट से जडेरूआ सहित अन्य गांवों को पानी दिया जा रहा है। जल संसाधन विभाग से निगम ने करार किया है कि सीवेज पानी को साफ कर उसे विभाग को सिंचाई के लिए देगा। इसके बदले में जल संसाधन विभाग नगर निगम को पेयजल मुफ्त देगा।

निर्माण कार्यों में होगा उपयोग

सीवेज के पानी का उपयोग जल्द ही शहर में होने वाले निर्माण कार्यों में भी किया जाएगा। इसके लिए निगम एसटीपी के साफ पानी को बेचेगा। इस पानी को टैंकरों के माध्यम से निर्माण स्थलों पर पहुंचाया जाएगा। फिलहाल इसकी योजना बनाई जा रही है।

सड़कें भी चमचमा रहीं

शहर से धूल-मिट्टी को कम करने के लिए तीन रोड सीपिंग मशीनें कार्य कर रही हैं। इस मशीनों में भी सीवेज के साफ पानी का उपयोग किया जाता है। इसी पानी से शहरभर की सड़कें साफ की जा रही हैं।

बैजाताल पर चलाई बोट

मोतीमहल स्थित बैजाताल में भी जलविहार स्थित प्लांट से सीवेज के साफ पानी को भरा गया है। इस पानी में बोट चलाकर नगर निगम 3 लाख 75 हजार कमा चुका है। साथ ही बैजाताल पर भी पर्यटक काफी संख्या में आने लगे हैं। यहां फव्वारे भी सीवेज के पानी से चलाए जा रहे हैं।

पांच सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट

स्थान	लालटिपारा प्लांट (चालू)
क्षमता	65 एमएलडी वाटर
लागत	55 करोड़ रुपए
फिल्टर	40 से 45 एमएलडी पानी प्रतिदिन
स्थान	जलालपुर प्लांट (चालू)
क्षमता	145 एमएलडी वाटर
लागत	100 करोड़ रुपए
फिल्टर	80 एमएलडी पानी प्रतिदिन
स्थान	जलविहार प्लांट (चालू)
क्षमता	1 एमएलडी वाटर
लागत	1.5 करोड़ रुपए
स्थान	ललियापुरा (निर्माणाधीन)
क्षमता	4 एमएलडी
लागत	3.5 करोड़
स्थान	शताब्दीपुरम (निर्माणाधीन)
क्षमता	8 एमएलडी
लागत	6 करोड़

इनका कहना है

सीवर ट्रीटमेंट प्लांटों से फिल्टर पानी की गुणवत्ता अच्छी है। हालांकि यह पानी पीने योग्य नहीं है, लेकिन इसका उपयोग खेती व अन्य कार्यों में किया जा रहा है। संभवत ग्वालियर प्रदेश का ऐसा पहला शहर है जो सीवेज पानी का पूरी तरह से उपयोग खेती व अन्य कार्यों में कर रहा है।

शिवम वर्मा, निगमायुक्त, ग्वालियर

-सरकार के तमाम दावों की खुल रही पोल

25 लाख किसानों को सम्मान निधि का इंतजार

प्रशासनिक संवाददाता, भोपाल

किसानों को लेकर मध्यप्रदेश सरकार कितनी गंभीर है, यह इससे ही समझा जा सकता है कि सात माह का इंतजार करने के बाद भी 25 लाख किसानों को मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना का पैसा अभी तक नहीं मिल पाया है। अब वित्त वर्ष समाप्त होने की वजह से इन किसानों को दो हजार रुपए का नुकसान होना तय है। इसके बाद भी अभी यह तय नहीं है कि आखिर उन्हें कब से सम्मान निधि की राशि मिलेगी।

गौरतलब है कि बीते साल प्रदेश के 28 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव के पहले जीत दर्ज करने के लिए किसानों को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सरकारी खजाने की दयनीय हालत होने के बाद भी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत किसानों को हर साल चार हजार रुपए मिलने हैं। उस समय सरकार का पूरा फोकस उन इलाकों में रहा, जहां पर उपचुनाव होने थे। उपचुनाव समाप्त होते ही सरकार ने उन किसानों को भुला दिया जिनको अब तक इस योजना के तहत राशि नहीं मिली है। ऐसे किसानों की संख्या करीब 25 लाख बताई जा रही है।

पहली किस्त ही नहीं मिली

अब सरकार को भी अपनी यह योजना भारी पड़

रही है। यही वजह है कि अब तक सरकार को आधा दर्जन से अधिक बार किसानों को पैसा देने के लिए कार्यक्रम आयोजित करने पड़े हैं, लेकिन फिर भी 24 लाख 69 हजार 580 किसानों को योजना की पहली किस्त नहीं मिल सकी है। कहा जा रहा है कि सरकार द्वारा कृषि विभाग को इस मद में राशि का आवंटन ही नहीं किया गया है। इसकी वजह से वित्त वर्ष की समाप्ति से पहले सभी किसानों को राशि भुगतान ही नहीं हो सका है।

पंजीयन के नाम पर अटकाया

प्रदेश के 28 लाख 14 हजार 858 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत पंजीकृत हैं। इन पंजीकृत किसानों की सूची भी प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र को दी गई थी। ऐसे में फिर से प्रदेश में किसानों का नए सिरे से पंजीयन का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। इसके बाद भी प्रदेश के किसानों का नाम अलग से पंजीकृत करने का काम शुरू कर दिया गया।

उठ रहा सवाल

उधर, इस मामले में सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों से पता चलता है कि वह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के आधार पर ही हैं। अब सरकार कह रही है कि जो किसान पीएम सम्मान निधि योजना के तहत पात्र हैं वह सभी किसान मुख्यमंत्री किसान कल्याण सम्मान निधि योजना के लिए भी पात्र माने गए हैं। अब सवाल यह है कि जब यह किसान पहले से ही पात्र हैं, तो उन्हें मुख्यमंत्री सम्मान निधि से वंचित क्यों रखा गया है।

82.15 लाख किसान पंजीकृत

मप्र में पीएम किसान सम्मान निधि योजना में कुल पंजीकृत किसानों की संख्या 82 लाख 14 हजार 858 है। इनमें से अब तक 57 लाख 45 हजार 278 किसानों को ही मुख्यमंत्री सम्मान निधि की राशि का भुगतान किया गया है। इस अवधि में किसानों को 1149 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके उलट केन्द्र सरकार द्वारा अब तक प्रदेश के किसानों को पीएम सम्मान निधि के तहत 8476 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है।

आवश्यकता

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर और मुरैना से प्रकाशित

जागत गांव हमार

कृषि और पंचायत पर आधारित साप्ताहिक समाचार पत्र के लिए जिला, जनपद स्तर पर संवाददाता चाहिए।

संपर्क करें

जबलपुर, प्रवीण नामदेव-9300034195
शहडोल, गोपाल दास बंसल-9131886277
नरसिंहपुर, प्रहलाद कौरव-9926569304
हरदा, राजेन्द्र बिल्लोरे-9425643410
विदिशा, अवधेश दुबे- 9425148554
सागर, अनिल दुबे-9826021098
राहतगढ़, भगवान सिंह प्रजापति-9826948827
दमोह, बंटी शर्मा -9131821040
टीकमगढ़, नीरज जैन -9893583522
राजगढ़, गजराज सिंह मीणा -9981462162
मुरैना, अवधेश दण्डोतिया -9425128418
शिवपुरी, खेमराज मौर्य-9425762414
भिण्ड- नीरज शर्मा-9826266571
खरगौन, संजय शर्मा-7694897272
सतना, दीपक गौतम-9923800013
रीवा-धनंजय तिवारी-9425080670
रतलाम, अमित निगम-70007141120
झाबुआ-नोमान खान-8770736925

कार्यालय का पताः- लाजपत भवन प्रथम तल, आईसीआईसीआई बैंक के पास, एमपी नगर, जोन-1, भोपाल, मप्र,
संपर्क करें- 07554064144, 9229497393, 9425048589

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादकः अजय कुमार द्विवेदी, संपर्क-9229497393, 9425048589, ईमेलः- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)